POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! काले धन के साथ काली नीयत की भी सफाई जरूरी है। हमने देखा, नोटबंदी के मुद्दे पर दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा का पूरा शीतकालीन सत्र किस तरह हंगामें की भेंट चढ़ गया।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

हंगामा करने वालों को संसद के बेशकीमती समय और जनता के पैसों की बर्बादी का बिल्कुल खयाल नहीं आया। इसमें सिर्फ राजनेताओं का निजी स्वार्थ और राजनीतिक लाभ लेने की नीयत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई।

नोटबंदी से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान यह तो अब सामने आएगा। असली काम भी अब शुरू होगा। किसने किस तरह से कालेधन को सफेद करने की जुगत की और किसने फिर से नए नोटों से कालाधन अपनी तिजोरी में भरा, सब सामने आएगा।

सरकार के 'मनी कमांडों' (आईटी, ईडी, आईबी, एयर इंटलीजेंस यूनिट और पुलिस) सब मिलकर काम कर रहे हैं और ब्लैक मनी रखने वालों की जानकारी दे रहे हैं।

यह भी सामने आ रहा है कि लालच में आकर कई लोगों ने भ्रष्टाचारियों का साथ दिया है जिनमें कई बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि काले कारनामें करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

जनता ने नोटबंदी को 'बोल्ड स्टेप' माना है और मोदी पर विश्वास जताया है। जल्द ही इसके कई फायदे दिखने लगेंगे।

देश में मार्च से शुरू होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक!

नोटबंदी के बाद देश में नए आइडिया और इनोवेशन के दम पर वित्तीय संस्थाएं कैशलेस इकोनॉमी का फायदा लेने में जुटी हैं। शहर हो या गांव सबको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का बेसब्री से इंतजार है। देशव्यापी पहुंच और लोगों से जुड़ाव के चलते यह किसी भी बैंक को पीछे छोड़ने में सक्षम हो सकता है। इस बैंक का काम-काज 2017 के मार्च महीने से शुरू होगा।

आईपीपीबी 400 करोड़ की इक्विटी पूंजी और 400 करोड़ के सरकारी अनुदान के साथ अपने काम-काज का श्रीगणेश करेगा। संगठन को यह अनुदान खासकर ग्रामीण भारत में टेक्नोलॉजी नेटवर्क स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। आईपीपीबी शहरों व दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक विभिन्न सेवाएं देगा। वैसे तो इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी मूल रूप से एक ही तरह के उपभोक्ता को अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन यह उपभोक्ता पर निर्भर करेगा कि वह इंडिया पोस्ट से बैंकिंग सेवाएं लेगा (जो कि वर्तमान में चल रही है) या फिर वह आईपीपीबी से वित्तीय लेन-देन करेगा।

सबसे बड़ा नेटवर्क

इंडिया पोस्ट के पास 154,939 पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इनमें 90 फीसदी पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाकों में है जिसका फायदा ग्रामीणों को मिलेगा।

समय पर स्पीड पोस्ट नहीं पहुंची, देना होगा 60 हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में भंवर लाल गोरा ने जीपीओ व मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के खिलाफ अपने वकील के जरिए परिवाद दायर किया। परिवाद में मंच को बताया गया कि परिवादी ने पोस्ट ऑफिस के जरिए स्पीड पोस्ट से 3 अप्रेल 2008 को ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपना आवेदन भिजवाया था। उनका आवेदन 5 अप्रेल को वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन डाक विभाग की लापरवाही से उसका आवेदन समय पर नहीं पहुंचा। उसने डाक विभाग से देरी का कारण पूछा तो सही जवाब नहीं दिया और कहा कि उसे पोस्टल चार्जेज लौटा दिया जाएगा।

उपभोक्ता मंच में मामले की सुनवाई पर विभाग ने दलील दी कि किसी कर्मचारी या अधिकारी ने जान-बूझकर गंतव्य स्थान पर डाक पहुंचाने में देरी नहीं की। वे स्पीड पोस्ट चार्ज 22 रुपए लौटाने के लिए तैयार हैं। मंच ने विभाग की इस दलील को नकारते हुए कहा कि डाक पहुंचने में देरी के कारण परिवादी संभावित नौकरी से वंचित रहा। सिर्फ चार्जेज लौटाने से विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उपभोक्ता मंच ने स्पीड पोस्ट, जीपीओ व मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को आदेश दिया कि वह भंवर लाल गोरा को 60 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करें।

औद्योगिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा और दक्षता जरूरी

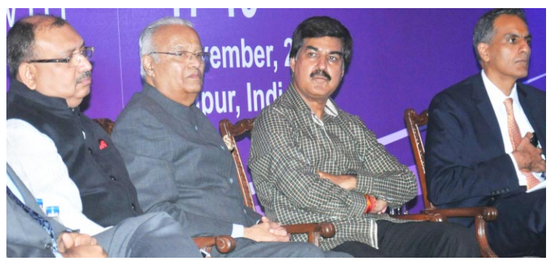

सरकार के नोटबंदी के फैसले से देश में डिजिटल इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे देश में नगदी रहित व्यवस्था तेजी से पैर पसारेगी। 'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप एस महता ने यह विचार 'कट्स' और भारतीय उद्योग परिसंघ 'सीआईआई' द्वारा 17 नवम्बर को आयोजित 'उत्तरी राज्य कैसे बने प्रतिस्पर्द्धी' विषयक सेमिनार में व्यक्त किए।

उन्होंने कहा देश में डबल डिजिट की ग्रोथ के लिए बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना और उनका वास्तविक विकास जरूरी है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास तेजी से बढ़ेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सरकार द्वारा राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा, निपुणता और दक्षता अनिवार्य है।

सेमिनार में अमरीकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने कहा कि भारत को उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिससे मध्यम वर्ग व पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा सके। योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं 'कट्स' के अध्यक्ष अरुण मायरा ने रोजगार सृजन को खास अहमियत देने की आवश्यकता जताई।

गांवों में होगा डिजिटल पेमेंट सिस्टम

नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार ग्रामीण इलाकों में लोगों को आधुनिक पेमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए कई उपाय करने जा रही है। इन उपायों में ग्रामीणों में नगदी रहित (कैशलेस) सिस्टम के प्रति जागरूकता पैदा करने और ट्रेनिंग देने से लेकर दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट के योग्य बनाने पर 100 रुपए प्रेरक स्वरूप दिया जाना आदि भी शामिल हैं।

ग्रामीणों को नगदी रहित लेन-देन करने की जानकारी और ट्रेनिंग देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिलों, तालूका और पंचायतों में कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिसका मकसद ग्रामीणों के बैंक खाते को मोबाइल और आधार नंबर से जोड़ना, रुपे कार्ड, पिन नंबर जारी करना और डाउनलोड करने के साथ सफल ट्रांजेक्शन कराना है।

फरवरी में पेश होगा आम बजट

इस बार आम बजट एक फरवरी को रखा जाएगा। जिसके मद्देनजर मोदी सरकार ने बजट सत्र जनवरी के अन्तिम सप्ताह में बुलाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक व्यक्तव्य में कहा गया है कि आम बजट को एक महीने पहले पेश किया जा रहा है ताकि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को तेजी से अमल में लाया जा सके। इस बार का रेल बजट भी आम बजट के साथ पेश होगा। यानी रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। राज्यों से भी आग्रह किया गया है कि इसका लाभ उठाने के लिए वे अपनी योजनाओं को इसी के अनुरूप आगे बढ़ाएं।

नरेगा में सूचना बोर्ड लगाना जरूरी

नरेगा योजना के तहत कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना पहले से अनिवार्य है। इसके बावजूद ज्यादातर कार्यस्थलों पर सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। पिछले दिनों नरेगा विभाग द्वारा किए गए जिलेवार सर्वे में कार्मिकों की यह लापरवाही सामने आई। केन्द्र सरकार भी इसके लिए नाराजगी जता चुकी है। अब ऐसे लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड पर कार्यस्थल पर स्थानीय सामग्री से निर्मित खर्च की जानकारी सार्वजनिक की जाती है। बाद में हुए खर्च को भी बोर्ड पर अपडेट करना जरूरी है।

जल के क्षेत्र में बनें आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि जिस ऐतिहासिक सफलता के साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ है उससे भी दोगुना जोश और जज्बे के साथ अभियान के दूसरे चरण में सभी को जुटना होगा। तभी हम प्रदेश को जल के क्षेत्र में स्वावलंबी और हरा-भरा बना पाएंगे।

सभी को मिलजुल कर इसे उस चरम तक ले जाना है कि हमें पानी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अभियान के तहत प्रदेश के 4200 गांवों और 66 नगरीय क्षेत्रों में जल स्वावलंबन के काम होंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनी है। इस चरण में एक करोड़ पौधे भी लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

भामाशाह योजना के बताएं फायदे

भामाशाह योजना में हस्तान्तरित फायदे ग्रामसभा में बताने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब लाभान्वित होने वाले लोगों के बारे में और उनको दिए गए लाभ के बारे में ग्रामसभा में जानकारी दी जा सकेगी। अगर संबंधित व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ है तो वह उस पर ऐतराज भी कर सकता है।

भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतरित फायदों पर प्रशासनिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जा सकेगी। रिपोर्ट ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी तैयार कर ग्राम सभा की बैठक के 15 दिन पहले ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराएगा। ग्रामसभा में इस रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया जाएगा।

शुरू होगी गरीब कल्याण योजना

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी शख्स 50 फीसदी टैक्स और पेनल्टी के साथ अपनी अघोषित काले धन का खुलासा कर सकता है। यह स्कीम 17 दिसम्बर से शुरू होकर 31मार्च, 2017 तक चलेगी।

इसमें उस शख्स की जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। अगर ब्लैक मनी के बारे में खुद ने नहीं बताया और पकड़े गए तो इस पर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी। 25 फीसदी रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाएगी। गरीब कल्याण योजना में राशि जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है।

नोटबंदी और गरीब

नोटबंदी से जहां कालेधन, आतंकवाद व भ्रष्टाचार पर जोरदार चोट की गई है वहीं इससे गरीबों को बेहद फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की गरीबी को कुछ हद तक दूर कर दिया। अब देखिए, देश में गरीबों के 24 करोड़ से भी ज्यादा जीरो बेलेंस खाते खोले गए।

मान लीजिए, उनमें से 10 करोड़ लोगों के खातों में दो-दो लाख रुपए की बेनामी राशि जमा हुई और उसके लिए उन्हें 20 फीसदी कमीशन दिया गया तो खाते में 40 हजार रुपए कमीशन के बच जाएंगे, जो गरीबों की गरीबी को दूर करेगा।

-घेवर चन्द गोदीका, जयपुर

गांवों को बनाया जाए स्मार्ट विलेज

राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि गांवों की उन्नति के लिए शहर के साथ गांव को भी स्मार्ट विलेज बनाया जाए। स्मार्ट विलेज में मूलभूत सुविधाओं के साथ जरूरत के मुताबिक उद्योग धन्धे हों। इससे स्वरोजगार को बल मिलेगा और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

उन्होंने स्वच्छता मिशन को सबकी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि खुले में शौच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। खुले में शौच से बीमारी जंगल से होकर घर तक आती है। सरकार शौचालय बनाने के लिए अनुदान दे रही है, मगर हमें ही बनवाने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना होगा।

जन-धन खातों में अब आएगा धन

नोटबंदी के बाद जन-धन खातों में जमा काले धन पर जल्द सरकार कोई फैसला कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बारे में संकेत दिए हैं। उन्होंने एक रैली में कहा कि 'मैं दिमाग खपा रहा हूं कि जन-धन खातों में जमा काला-धन कैसे गरीबों का हो जाए'।

सरकार गरीबों के जीरो बेलेंस खातों में पैसा ट्रांसफर करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ट्रांसफर होने की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने रुपए आते हैं। रोजगार योजनाओं पर भी पैसा खर्च होगा जिससे गरीबों को रोजगार मिल सके।

महिलाओं के लिए अच्छी खबर

गर्भावस्था में इलाज के खर्च से परेशान महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब देशभर में हर गर्भवती महिला के उपचार का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। डॉक्टर रिकार्ड को देखकर महीने की नौ तारीख को जांच के लिए खुद घर-घर जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉंच मोबाइल एप व पोर्टल से ऐसा संभव होगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर